भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4217

मंगलवार, 19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

ओएनडीसी प्लेटफॉर्म

4217. श्री पी. सी. मोहनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं और संगठनों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) कर्नाटक, विशेषकर बंगलौर शहरी और बंगलौर सेन्ट्रल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में नामांकित ऐसे विक्रेताओं की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने ओएनडीसी पर छोटे खुदरा विक्रेताओं और रेहड़ी-पटरी वालों के नामांकन को प्रोत्साहित करने के लिए कोई लक्षित जागरूकता या ऑनबोर्डिंग अभियान चलाया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लाभार्थियों की संख्या और कवर किए गए स्थानों सहित ऐसी पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ओएनडीसी प्लेटफॉर्म से लाभान्वित होने के लिए पारंपरिक खुदरा विक्रेताओं के लिए डिजिटल क्षमता निर्माण और पहुँच को आसान बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) कोई प्लेटफॉर्म या एप्लिकेशन या मार्केटप्लेस नहीं है, बल्कि यह एक नेटवर्क है जो विभिन्न प्लेटफार्मों पर मौजूद क्रेताओं और विक्रेताओं को परस्पर जोड़ता है। पारंपरिक प्लेटफॉर्म-केंद्रित मॉडलों के विपरीत, ओएनडीसी एक खुला, इंटरऑपरेबल नेटवर्क है, जो छोटे व्यवसायों को एक ही प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहे बिना डिजिटल कॉमर्स में भाग लेने की सुविधा प्रदान करता है। इसलिए, ओएनडीसी उपभोक्ताओं/क्रेताओं की संख्या को ट्रैक नहीं करता है। 10 अगस्त 2025 तक की स्थिति के अनुसार, पूरे भारत के 630 से अधिक शहरों और कस्बों के 7.5 लाख से अधिक विक्रेता और सेवा प्रदाता इस नेटवर्क पर लाइव हैं। इनमें से 1.2 लाख से अधिक विक्रेता खुदरा क्षेत्र में हैं।

(ख): 10 अगस्त 2025 तक की स्थिति के अनुसार कर्नाटक में कुल 21,800 से अधिक विक्रेता ओएनडीसी नेटवर्क पर लाइव हैं, जिनमें बेंगलुरु के 19,700 से अधिक विक्रेता शामिल हैं।

(ग) से (ङ): जी, हां। सरकार ने छोटे रिटेलरों और स्ट्रीट वेंडरों में जागरूकता बढ़ाने और ओएनडीसी को अपनाने वालों की संख्या में वृद्धि करने के लिए कई उपाय किए हैं। एमएसएमई मंत्रालय की 'एमएसएमई व्यापार सक्षमता और विपणन पहल (एमएसएमई टीम)' स्कीम, एमएसएमई को ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर शामिल करने और उनकी ई-कॉमर्स यात्रा में सहायता करने पर केंद्रित है। यह एमएसएमई को विभिन्न बाजारों तक पहुंच बनाने में सहायता करके, उन्हें अपना ग्राहक आधार बढ़ाने और अपनी आय में वृद्धि करने में सक्षम बनाता है। यह एमएसएमई की डिजिटल मौजूदगी और लेनदेन का लेखा-जोखा (ट्रांजैक्शन हिस्ट्री) स्थापित करके उनकी विश्वसनीयता और साख को भी मजबूत करेगा। इस स्कीम का परिव्यय 277 करोड़ रुपए है। इसके द्वारा 5 लाख एमएसएमई लाभार्थियों (50% महिलाओं के लिए है) को लाभ प्रदान करने का लक्ष्य है।

एमएसएमई टीम पहल के अंतर्गत टियर-II और टियर-III शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों सहित विभिन्न स्थानों पर डिजिटल साक्षरता और ई-कॉमर्स परिचालन पर प्रशिक्षण अंतर्निहित है। 23 जुलाई, 2025 तक की स्थिति के अनुसार एमएसएमई टीम पोर्टल पर ऑनबोर्ड एमएसएमई की संख्या 2834 है, जिनमें से 1068 महिला स्वामित्व वाले उद्यम हैं। 28 जुलाई, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, टीम स्कीम के अंतर्गत जागरूकता संबंधी 24 कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं।

इसके अतिरिक्त, ओएनडीसी ने डिजिटल कॉमर्स तक सभी की पहुंच संभव बनाने के बड़े अभियान के भाग के रूप में देशभर के विक्रेताओं, कारीगरों और ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमियों के लिए क्षमता निर्माण संबंधी पहलें भी की हैं। ओएनडीसी ने विक्रेताओं (विशेष रूप से पहली बार के विक्रेताओं) को डिजिटल कॉमर्स में सफल होने में मदद करने के लिए 14 भाषाओं में एक पुस्तिका भी तैयार की है। ओएनडीसी ने भारतीय भाषाओं में ऐप विकसित करने और ई-कॉमर्स को बेहतर बनाने के लिए भाषिणी से साझेदारी की है। क्रेताओं और विक्रेताओं को ओएनडीसी के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करने हेतु व्हाट्सएप बॉट "ओएनडीसी सहायक" को 5 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के साथ विकसित डिजिटल तैयारी मूल्यांकन उपकरण, कारीगरों और एमएसएमई की डिजिटल क्षमताओं का आकलन करने और वृद्धि करने में मदद करता है, ताकि उनकी सतत डिजिटल वाणिज्य भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इन पहलों को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि समस्त

भारत के ग्रामीण उद्यमी और छोटे व्यवसाय सशक्त बनें और ओएनडीसी द्वारा तैयार किए गए डिजिटल कॉमर्स ईकोसिस्टम में शामिल हों और इसका लाभ उठाएं।

*****